

बिहार विधान परिषद

(199वां शीतकालीन सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

30 नवंबर, 2021

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य - विधि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग].

Total Short Notice Question- 6

शीघ्र जीर्णोद्धार

*1 मो. फारूक (विधान सभा):

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला के डुमरी कटसरी प्रखंड के नया गांव में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र में 5 कट्टा जमीन में भवन है जिसकी स्थिति काफी जर्जर है एवं भवन के जीर्णोद्धार की अत्यंत आवश्यकता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस भवन का शीघ्र जीर्णोद्धार करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सीरो सर्वे की व्यवस्था

*2 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के पीक समाप्त होने और टीकाकारण की बढ़ती रफ्तार के बीच सभी जिलों में सीरो सर्वे कराने की तैयारी शुरू की थी, लेकिन वह गति नहीं पकड़ सकी है;

(ख) क्या यह सही है कि सीरो सर्वे के तहत व्यक्ति में एंटीबॉडी के विकसित होने का सर्वेक्षण किया जाता है, इसके तहत निर्धारित क्षेत्रों या जिले में चयनित व्यक्तियों के समूह

के बीच से एंटीबॉडी के विकास की जांच को लेकर सैंपल एकत्र किया जाता है, फिर इस सैंपल की लैब में जांच कर प्राप्त नतीजों का अध्ययन किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर इससे जुड़ी तैयारियों व सावधानी की वकालत की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही स्वास्थ्य विभाग सीरो सर्वे कराने की कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में सीरो सर्वे कराने का विचार रखती है?

डबल डोज एवं बूस्टर डोज की व्यवस्था

*3 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के लोगों के लिए कोरोना टीका का बूस्टर डोज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में 18 वर्ष से कम आयुवर्ग के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान नगण्य है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य की आधी आबादी अभी भी कोरोना टीकाकरण की पहुंच से दूर है;

(घ) क्या यह सही है कि राज्य में मात्र 20% लोगों ने ही कोरोना टीका का डबल डोज लिया है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतलाएगी कि राज्य के लोगों को कोरोना टीका का डबल डोज कबतक मिल जाएगा तथा बूस्टर डोज की व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाए गये हैं और नहीं तो क्यों?

प्रोत्साहन नियमावली बनाने पर विचार

*4 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):

क्या ऊर्जा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर

ऊर्जा के विकास एवं प्रसार हेतु सतत प्रयास कर रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बहुमंजिले निजी एवं सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने हेतु प्रोत्साहन नियमावली बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों?

निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

*5 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के कर्मियों की तरह बिहार सरकार के कर्मियों को भी सारी सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को निःशुल्क अंतर्वासी/बर्हिवासी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को निःशुल्क अंतर्वासी/बर्हिवासी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं की तरह राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

मुआवजा देने का विचार

*6 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

क्या गन्ना उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि प्रदेश में इस वर्ष बाढ़ के चलते समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, बक्सर एवं गोपालगंज में करीब 88 करोड़ रुपये की गन्ने की खेती बर्बाद हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के 1054 पंचायतों के 48781 हेक्टेयर रकबे में गन्ने की खेती सीधे तौर पर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभागों को शीघ्र क्षतिपूर्ति/मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?
